



जागत

हमारा



चौपाल से
भीपाल तक

भीपाल, सोमवार 05-11 सितंबर 2022, वर्ष-8, अंक-22

भीपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज बोले-बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावितों के साथ खड़ी राज्य सरकार

प्रदेश के किसानों को जल्द मिलेगी गेहूं और जौ की नई किस्में

विदिशा को 11.3 करोड़ की राहत

फसल का 16 हजार रु. हेक्टे. मिलेगा मुआवजा

सरकार की हमारी पहली प्राथमिकता है जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करना

हिदायत-प्रभावित जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे

भीपाल। जागत गांव हमार

मग्न में बीते दिनों आई बाढ़ से प्रदेश के हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मकान, दुकान से लेकर जानवरों और फसलों को भी नुकसान हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के 14 हजार 419 बाढ़ प्रभावितों को राहत दी। उन्होंने 11 करोड़ 3 लाख 15 हजार रुपए की राशि बाढ़ प्रभावितों के खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से घर, घरेलू सामान, फसल और पशुओं की बहुत हानि हुई है। हमारी पहली प्राथमिकता नुकसान की भरपाई करना है। राज्य सरकार संकट के समय प्रदेशवासियों के साथ है। जिलों के प्रभारी मंत्री राहत के लिए सर्वे की मॉनिटरिंग करें। राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त दल से क्षति का आकलन कराया जाए। इस प्रक्रिया में नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। सर्वे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सूची चर्या की जाए और सूची में उल्लेखित नाम ग्रामवासियों को पढ़ कर सुनाए जाए, यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसकी आपत्ति को सुना जाए।



घर भी बनवाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा सहित प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 16 हजार रुपए हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बाढ़ से गिरे मकानों को प्रधानमंत्री आवास की तरह बनवाया जाएगा। बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आरबीसी की धारा 6.4 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मकान क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख रुपए से अधिक की राशि दी जा रही है। गांवों में पीएम आवास की तरह बाढ़ पीड़ितों के नए मकान बनवाए जाएंगे।

खाते में राहत राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने, दवा छिड़कने, पेयजल की आपूर्ति और इलाज की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके आवास बनने तक अस्थाई आवास की व्यवस्था की जाए। राहत के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के 534 गांवों के 14 हजार 419 लाभार्थियों को 11 करोड़ 3 लाख 15 हजार रुपए की राहत राशि सिंगल बिलक से उनके खाते में राहत राशि डाली। वहीं कलेक्टर ने जानकारी दी कि अभी तक के सर्वे में जिले में कुल 910 गांवों के 22 हजार 443 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

- प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग करें प्रभारी मंत्री
- बारिश-बाढ़ से क्षति का आकलन करने के लिए संयुक्त दलों का गठन किया जाए
- राजस्व, कृषि, उद्यानिकी, पंचायत विभाग का संयुक्त दल बनाकर जिलों में सर्वे करें
- बाढ़ प्रभावितों की सूची पंचायत भवन व नगरों में सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाए
- बाढ़ प्रभावितों की पूरी सूची बनाकर चर्या करें और ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाएं
- सीएम ने की घोषणा-किसानों को फसल बीमा का लाभ भी दिलाएंगे
- मुख्यमंत्री ने हिनोतिया और गुजरखेड़ा ग्राम में लिया नुकसान का जायजा
- जो भी बाड़ से प्रभावित हुए हैं उन्हें यथा संभव सहयोग किया जाएगा
- बाढ़ से गिरे मकानों को प्रधानमंत्री आवास की तरह बनवाया जाएगा

जौ का होगा अच्छा उत्पादन, जिनक-आयलन भरपूर

बियर बनाने के लिए डीडब्ल्यूआरपी 137 उपयोगी

भीपाल। प्रदेश के किसानों का जल्द ही गेहूं व जौ की नई किस्में मिलने वाली हैं। जो उत्पादन के मामले में किसानों की आय बढ़ाएंगी और पोषिकता के मामले में आमजन का स्वास्थ्य बनाएंगी। करनाल से आए डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि गेहूं व जौ में नई वैरायटी रिलीज की जा रही है। डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह बताते हैं कि डीडब्ल्यूआरपी 137 की किस्म हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में अच्छी पैदावार दे रही है। इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है। इसकी नवंबर में बुवाई हो जाती है और 125 दिन में फसल तैयार हो जाती है। खासियत यह है कि इस फसल से बेबी फूड, बियर और खाने में उपयोग ली जाती है। बियर बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल के रूप में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इन वैरायटियों की उत्पादन क्षमता फिफ्टेयर आठ टन प्रति हेक्टेयर है। 38 डिग्री तापमान होने पर भी इसकी उत्पादन क्षमता नहीं गिरेगी। 125 दिन में फसल पककर तैयार होगी और बोवनी का काम अक्टूबर में किया जा सकता है। डीडब्ल्यूआरपी 303 किस्म में जिनक का मात्रा 12 पीपीएम और आयलन कंटेंट 0.40 पीपीएम उपलब्ध है। यह बायोफोटोफाइट किस्मों में शामिल है।

यह वैरायटी आ रही

- डीबीडब्ल्यू 327, 303 की वैरायटी हरियाणा, दिल्ली में इसकी पैदावार अच्छी है।
- डीबीडब्ल्यू 187 यूपी, विहार, बंगाल, अब मग्न में भी इसकी पैदावार बढ़ाई जाएगी।
- डीबीडब्ल्यू 222 गेहूं की वैरायटी भी जल्द मग्न में किसानों का उपलब्ध कराई जाएगी।

रीवा को घोषित करें सूखाग्रस्त

सीएम से नर्मदापुरम और रीवा के विधायकों ने की मांग, त्योंथर विधायक बोले-किसानों को दी जाए राहत राशि

भीपाल। मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा संगठन की मजबूती में जुट गई है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने रीवा और नर्मदापुरम जिले के विधायकों के साथ बैठक की। सीएम से रीवा जिले के आठ विधायकों ने कहा कि विंध्य इलाके में कम बारिश हुई है। रीवा जिले में सूखे जैसे हालात हैं। विधायकों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। सीएम हाउस में बैठक के बाद त्योंथर के विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि रीवा के विधायकों की मांग है हमारे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें। रीवा क्षेत्र में कम बारिश की वजह से किसानों के फसलें सूख गई हैं। किसानों के नुकसान की राहत राशि दी जाए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सूखा राहत देने की बात कही है।

राष्ट्रीय बीज निगम को मुरैना के पांच गांवों में 5525 बीघा बीहड़ दिए गए

चंबल के बीहड़ों में होगी तिलहनी बीजों की खेती

अवधेश उडोतिया, मुरैना। जागत गांव हमार

चंबल के बीहड़ों में कृषि मंत्रालय तिलहनी बीजों की खेती करवाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) को मुरैना जिले के पांच गांवों में 1105 हेक्टेयर (5525 बीघा) बीहड़ दिए गए हैं। सबसे पहले लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च कर जमीन को खेत बनाने के लिए समतल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कृषि मंत्री व क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर छह सितंबर को करेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम ने जिले के बीहड़ों में बीज फार्म की योजना 2020 में तैयार की थी।



एनएसजी ने बीज फार्म हाउस के लिए जिला प्रशासन से आठ हजार (40 हजार बीघा) हेक्टेयर जमीन मांगी थी, लेकिन प्रशासन 1105 हेक्टेयर बीहड़ की जमीन देने पर ही सहमत हुआ है। इसी क्रम में जखोना, रिठौरा, गड़ौरा और गुर्जा गांव के पास 855 हेक्टेयर (4275 बीघा) बीहड़ भूमि आवंटित की गई है, पिंपरई गांव में 250 (1250 बीघा) हेक्टेयर जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, जो इस पखवाड़े पूरी हो जाएगी। दो साल बाद यहां तिलहनी बीजों की खेती का काम शुरू हो जाएगा। एक साल से ज्यादा समय इन बीहड़ों को समतल करके खेत बनाने में खर्च हो जाएगा।

जखोना, रिठौरा, गड़ौरा और गुर्जा में 855 हेक्टेयर जमीन एनएसजी को आवंटित कर दी है। पिंपरई गांव में 250 हेक्टेयर जमीन आवंटन जल्द कर दिया जाएगा। नरोतम भार्गव, अपर कलेक्टर, मुरैना हमने तो आठ हजार हेक्टेयर जमीन मांगी थी, जिसमें से 1105 हेक्टेयर जमीन मिली है। सबसे पहले बीहड़ों को समतल करने का काम होगा। चंद्रशेखर, एनएसजी के एजीएम व प्रोजेक्ट इंचार्ज

केंद्र खर्च करेगा 100 करोड़ रुपए

बीहड़ों को समतल करके उनमें बड़े-बड़े फार्म हाउस (खेत) बनाए जाएंगे। इस जमीन में कृषि विभाग, एनएसजी और आवंटित अनुसंधान केंद्र के कृषि विज्ञानियों, तिलहनी बीजों की खेती के विशेषज्ञों की निगरानी में सरसों, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, सोआ, सनपत्तावर आदि फसलों के उन्नत किस्म में बीज तैयार किए जाएंगे, जो कम समय, कम सिंचाई में अधिक पैदावार दें। इस पूरे प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 40 फीसद बजट बीहड़ों को समतल करने में खर्च होगा। बीज निगम बीजों की खेती मुरैना जिले के किसानों से ही कराएगा। खेती लायक बनाने के बाद अंचल के किसानों को जमीन लीज पर दी जाएगी।

फसल में पीला मोजेक वायरस ने किसानों को चिंता में डाला

उज्जैन के बड़नगर में रोग और कीट से सोयाबीन सूखने की कगार पर

चंदना बुजेल परमार, उज्जैन। जागत गांव हमार

जिले के बड़नगर में सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। सोयाबीन की फसल में इस बीमारी के प्रकोप से किसानों के चेहरे लटकते हुए हैं। किसानों के हिलों की बात करती सरकार के कर्मचारी व जनप्रतिनिधि सिर्फ किसानों के लिए समर्पित और किसान मित्र बनने का दावा दिखावा कर फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। यह बात विधायक मुरली मोरवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के निरीक्षण के दौरान कही।

विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को किसानों के हित में रिपोर्ट भेजने की बात कही। साथ ही अधिक से अधिक बीमा राशि की भी मांग की। ग्राम बालोदाकोरन के किसान तुफान चौधरी ने बताया कि लगभग 10 बीघा के सोयाबीन में पीला मोजेक रोग और तना छेदक कीट के कारण अफरलीय और छोटी रह गई।

किसानों ने विधायक से मांग की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा अधिक से अधिक मिले, ताकि सोयाबीन के हुए नुकसान की भरपाई हो सके। क्षेत्र के गांव बालोदा लम्खा, बालोदा कोरन, भाटपचलाना, निरोला, अजड़ावदा, सुंदराबाद, खेड़ावदा, बड़गांवा, बरंडिया आदि गांवों में सोयाबीन फसल में पीला मोजेक से सूखने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सभी दवाओं का स्प्रे करने के बाद भी रोग जस के तस है।



तेज वर्षा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा

उज्जैन में इस बार अनुकूल वर्षा व मौसम के चलते पीला सोना खेतों में लहलहाने लगा था। करीब 45 से 50 दिन के पौधों में फूल व फली आ गई थी। बंपर फसल की आस पर बीते सप्ताह की लगातार तेज वर्षा ने पानी फेर दिया। क्षेत्र में अनेक जगह

पौधे आड़े पड़ गए, जिससे फूल फली जमीन पर गिर गई। मौसम खुलते ही खेतों में पीला मोजेक वायरस देख कर किसान निराश हो गया। जिले में करीब 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई है, जो कि अगले माह तैयार होने को है।

इन्होंने देखी स्थिति

इस दौरान विधायक के साथ कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुरेंद्र कौशिक, सहायक कृषि संचालक नरेश भोगा, एमसी काग कृषि विभाग बड़नगर, मोतीलाल कटारा नाथ तहसीलदार, रतन गीयल, प्रहलादसिंह देवड़ा जनपद सदस्य, सरपंच बुजलाल चौहान, बालाराम परमार, डॉ. नरेंद्रसिंह राठौर, वाल्मिक कौशिक, सुजानसिंह राठौर, देवेंद्रसिंह, हरपालसिंह, बालाराम चौधरी आदि उपस्थित थे।

उत्पादन प्रभावित कर दिया

फूल व फली भी आने लगी है। इसी दौरान बीते दिनों की तेज वर्षा ने उत्पादन को प्रभावित कर दिया है। किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। चिकली के किसान रामसिंह आंजना ने बताया कि क्षेत्र में पीले मोजेक वायरस ने सोयाबीन के पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। पौधे तेज वर्षा में आड़े पड़ गए, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। चंदेसरा के किसान नंदकिशोर पटेल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में 95-60 वैरायटी की सोयाबीन की बोवनी हुई है। उसमें पीले मोजेक की शिकायत ज्यादा है। माना जा रहा है जिले में करीब 10 फीसद क्षेत्र में पीले मोजेक वायरस का प्रकोप है।

क्षेत्र में सोयाबीन फसल में बहुत नुकसान हुआ है। यह पीला मोजेक वायरस में स्पेम फलाई बहुत ज्यादा अटेक से समस्या पैदा हुई है और इस पर अब नियंत्रण मुश्किल है। किसानों को इससे बहुत नुकसान होगा।

— डॉ. सुरेंद्र कुमार कौशिक, कृषि वैज्ञानिक उज्जैन

क्षेत्र में सोयाबीन फसल का नुकसान बहुत अधिक हुआ है। फसलों के भाव नहीं होने के कारण किसान पहले से ही परेशान हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा और प्रयासवादा दिलाए का पूरा प्रयास करूंगा।

— मुरली मोरवाल, विधायक

अब मछली पालन और सिंचाई की खेती करेंगे किसान

नवाचार: तालाबों की ग्रामीण ही करेंगे देखरेख

ग्वालियर का अमृत सरोवर बेरोजगारों को देगा रोजगार

दिव्या मिश्रा, ग्वालियर। जागत गांव हमार

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया। अब यह अमृत सरोवर किसानों और बेरोजगारों के लिए आमदनी और रोजगार का जरिया भी बनेंगे। जिला पंचायत के माध्यम से आठ से 10 लोगों का उपयोगिता समूह (यूजर्स ग्रुप) बनाकर एक सरोवर सौंपा जाएगा। यह समूह इन सरोवरों में मछली पालन, सिंचाई की खेती आदि कर सकेंगे। इससे दो फायदे होंगे। अमृत सरोवरों की देखभाल हो सकेगी और किसानों-बेरोजगारों को आमदनी और रोजगार मिलेगा। ग्वालियर जिला पंचायत ने उपयोगिता समूहों के लिए किसानों का चयन कर लिया है। इस माडल को मनरेगा के जरिए पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सरोवरों से रोजगार का सृजन वाले इस नवाचार के लिए ग्वालियर जिले में बनाए जा रहे 102 सरोवरों में किया जाएगा।



हर जिले में होंगे 75 सरोवर

अफसरों का दावा है कि अधिकांश सरोवरों का काम पूरा हो चुका है। ग्वालियर जिले में अपेक्षाकृत कम बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सरोवरों का जल स्तर कम है। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करवाया जाना है। जिससे कि गर्मी के समय में होने वाले पानी कमी को दूर किया जा सके।

ग्रामीणों को प्रशिक्षण मिलेगा

एक अमृत सरोवर का जिम्मा आठ से दस ग्रामीणों को दिया जाएगा। पहले इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, मछली पालन या सिंचाई की खेती के लिए बीज भी जिला पंचायत की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद खेती शुरू करते ही रखरखाव का पूरा जिम्मा इन्हीं ग्रामीणों का होगा। जिला पंचायत के प्रोजेक्ट ऑफिसर विनीत गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए ग्रामीणों का चयन भी कर लिया गया है।

अमृत सरोवरों में मछली पालन व आमदनी से जुड़ी गतिविधियां करने के लिए प्रदेशभर में प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण इन तालाबों की देखरेख करेंगे और इसके जरिए उनका तालाबों से जुड़ाव भी होगा। यह बेहतर नवाचार होगा।

सूफिया फारूकी, एमडी, मनरेगा, मप

अमृत सरोवर का कार्य जिले में लगभग पूरा हो गया है, जिन्हें अब रोजगार से जोड़ा जा रहा है। पंचायत की ओर से मछली पालन व खेती ग्रामीणों से कराई जाएगी जिससे उनकी आय बढ़ेगी। इसके लिए उपयोगिता समूह भी बना रहे हैं।

आशीष तिवारी, सीईओ, जप, ग्वालियर

जैविक खेती करने वाले को मिला प्रशिक्षण

खरगोन में प्राकृतिक खेती का किसानों का पढ़ाया पाठ

-खरगोन, भगवानपुरा और भीकनगांव के 90 किसान हुए शामिल

संजय शर्मा, खरगोन। खरगोन में आत्मा परियोजनांतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र में विखं भगवानपुरा, भीकनगांव एवं खरगोन के प्राकृतिक खेती के पंजीकृत कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा एमएल चौहान द्वारा कृषकों को प्राकृतिक खेती करने के लिए कम लागत की जैविक कीटनाशक दवाइयों ट्रायकोडर्मा, बायों फर्टिलाइजर, ड्रिफ्टमोजर का उपयोग किया जाए एवं जैविक खेती के लिए एक देशी गाय को पालना आवश्यक है। केवीके के कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीएस कुलमी द्वारा किसानों को बताया गया कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से खेती करके किसान अपनी लागत कम कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के

अंग बीजामृत व जीवामृत आच्छन्दन बनाने, अंतरवर्ती फसल पद्धति अपनाने के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही रोग कीट प्रबंधन के लिए किसानों को पांच पत्ती काड़ा, दशपर्णी अर्क, अमृत पानी निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि-अस्त्र, फसल की सुरक्षा के लिए जैविक कीटनाशक बनाना बताया गया। किसानों को प्राकृतिक कृषि के केवीके में स्थित फार्म फ़िल्ड में लगी फसलें कपास और सोयाबीन की अतवर्तीय 30 प्रजातियों की फसल प्रदर्शन के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। किसानों को जीवामृत का प्रयोग करके बताया गया। मृदा सौलंकी, उप परियोजना संचालक आत्मा प्रकाश ठाकुर सहायक संचालक कृषि, थान सिंह मंडलोई अनुविभागाध्यक्ष, भीकनगांव एवं खरगोन के आत्मा के समस्त वीटीएम, एटीएम एवं 90 कृषक मौजूद थे।

आठ रुपए प्रति किलो लहसुन बेचने को मजबूर

लहसुन के दाम ने निकाले किसानों की आंखों से आंसू

मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर से परेशान नजर आ रहा है, और इस बार उसकी परेशानी का कारण है उसे उसकी फसल का उचित मूल्य न मिलना। लहसुन के किसानों की आंखों से इन दिनों आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने लहसुन की फसल लगाई थी, उस लहसुन की कीमत ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चाहे मौसम की मार हो या फिर यूरिया की कमी सभी परेशानियों का सामना किसानों को जरूर करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि अब किसान अपने खेतों को बेचकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कोई अन्य रास्ता ढूँढ रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं।



लहसुन-प्याज की गिरती कीमतों पर चिंतित कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात



भोपाल। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री तोमर को प्रदेश में लहसुन-प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियों से अवगत कराया।

केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लहसुन-प्याज जैसे फसलों के लिये मिश्रित योजना बना कर क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक उत्पादन होने पर उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड-स्टोरेज की सुविधाएँ मुहैया कराई जानी चाहिये। साथ ही प्रीजर की सुविधा होने पर 20 से 25 क्विंटल की उपज को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी और किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकेगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कृषि मंत्री श्री पटेल को आश्वासित किया कि किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

दिग्विजय सिंह सीएम को लिखी चिठी

उचित कीमत दिलाने की पहल करे सरकार



इधर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश में लहसुन और प्याज की किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही है। रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर की मंडियों में किसान थोक में एक रुपए किलोग्राम की दर से लहसुन बेच रहे हैं। यही स्थिति प्याज को लेकर भी बन रही है। इससे किसानों की लागत तक नहीं मिल रही है। किसान उपज को नदी में फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार लहसुन और प्याज उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने की पहल करे। उन्होंने कहा कि किसान लगातार लागत मूल्य दिलाने की मांग कर रहे हैं पर कोई नीतिगत निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। प्रदेश में अब बड़ी संख्या में किसान ग्रीष्मकालीन मृग की खेती कर रहे हैं पर समय पर कभी समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी नहीं होती है।

सरकार किसानों को अधिक फसल पैदा करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। किसानों के लिए अधिक उत्पादन खराब है। किसानों ने लहसुन के बीच महाराष्ट्र से खरीदे हैं और मुनाफे की उम्मीद में कर दी बावनी।

राजकुमार सागर, सहायक प्रबंधक, कृषि विभाग, सीहोर

भाजपा ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। परन्तु आज अज्ञातताओं की हालत बहुत खराब है। प्याज-लहसुन में लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार लगातार किसानों को शोषण कर रही है। कुणाल चौधरी, विधायक, कालीपौल

कांग्रेस के द्वारा सिर्फ किसानों के नाम पर राननीति की जाती है। अभी कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों को छला गया है। भाजपा काम में विश्वास करती है और किसानों के साथ कठे से कठे मिलाकर खड़ी है।

-गिरिराज मंडलौरी, पूर्व विधायक

फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान, -सीहोर में 60 फीसदी होता है लहसुन का उत्पादन

भोपाल। जगत गांव हमार

भोपाल की नवंबर सस्की मंडी में भोपाल के आसपास और दूसरे जिलों से भी सब्जियां आती हैं, लेकिन वर्तमान में सस्की मंडी में दूर-दूर तक लहसुन से भरे बोरे ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि पैदावार ज्यादा होने और बाहर निर्यात न होने के चलते किसानों के पास सस्ते दामों में मंडी में अपने लहसुन को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस साल मार्च में किसान महेंद्र वर्मा ने फसला किया कि लहसुन की खेती में निवेश करना सही है, क्योंकि इसकी कीमत बाजार में बढ़ रही थी। छह

महीने बाद महेंद्र को अब अपने फसले पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि अच्छी कमाई की उम्मीद में उन्होंने जो लहसुन उगाया वो अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रफीकगंज गांव में उनके घर पर बिना बिका पड़ा है। मार्च में लहसुन अस्सी रुपए प्रति किलो पर बिक रहा था। उनके जैसे कई किसानों ने लहसुन बोने का फैसला किया। महेंद्र बताते हैं कि फसल अच्छी थी, और मेरे पास बेचने के लिए 80 बोरी यानी 4,000 किलो उपज है। लेकिन आज, बेहतर होगा कि मैं लहसुन को फेंक दूँ, क्योंकि कीमत बहुत कम है। उन्होंने

अफसोस जताया। लहसुन किसान इस उम्मीद में जो रहा है कि कीमतें फिर से बढ़ेंगी और उसके पास घर पर लहसुन का जो स्टॉक है, उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि उत्पादन मांग से बहुत अधिक होगा, तो मैं अलग तरह से काम करता। वर्मा अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के लाखों किसान बाजार में लहसुन की भरमार को देख रहे हैं और भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सीहोर जिले में हाडवे के किनारे लहसुन के ढेर सड़ रहे हैं जहां किसानों ने उन्हें फेंक दिया है। सिहोर जिला भारत के

लहसुन बेल्ट का हिस्सा है जिसमें मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन जैसे जिले और राजस्थान में झालावाड़, बारां और कोटा जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 2021-22 में 20,16,130 टन लहसुन का उत्पादन किया, जो भारत में कुल लहसुन उत्पादन का 62.85 प्रतिशत है। राजस्थान ने इसी अवधि में 5,39,180 टन लहसुन का उत्पादन किया। इन दोनों राज्यों में भारत में लहसुन के कुल उत्पादन का 78 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

साहूकारों से भी लिया कर्ज

वर्मा के लिए, लहसुन की भरमार ने बिना रुके तबाही मचा दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पांच एकड़ जमीन में लहसुन उगाने के लिए 200,000 रुपए से अधिक खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस साल लहसुन और प्याज की बुवाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और कुछ साहूकारों से 200,000 रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। किसान ने कहा कि कुछ भी नहीं करना बेहतर है, क्योंकि खेती अपनी तरह के संकट के अलावा कुछ नहीं ला रही है।

सरकार से गुहार

रफीकगंज गांव की 35 वर्षीय किसान बबली बाई के घर में लहसुन की 100 बोरियां रखी हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में लहसुन की जो कीमत मुझे मिल रही है, वो मजदूर की लागत भी नहीं निकाल पाएगी। मैंने लहसुन खुदाई के लिए बहुत खर्च किया है। इसलिए किसान अपनी उपज को फेंक रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि हमें हमारी मेहनत का सही दाम मिले। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे उनकी पढ़ाई और घर के अन्य खर्चों को चलाना मुश्किल हो रहा है।

डिफाल्टर होने का डर

सीहोर के राम शंकर जाट ने बताया कि सात हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से 6 क्विंटल बीज लिया था। लहसुन का उत्पादन भी कम हुआ है। जब हम मंडी में 80 की दूरी से बेचने आए हैं तो हमें 21 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। 60 क्विंटल लहसुन है, जबकि प्रति एकड़ खर्च 85 हजार लगा है। सोयाबीन 20 एकड़ बारिश की वजह से खराब हो गई। हमारे ऊपर 5 लाख का क्रेसीसी का कर्ज है। साहूकार के कर्ज लेकर भरंगे नहीं तो डिफाल्टर हो जाएंगे।

एमएसपी में लहसुन नहीं

लहसुन एमएसपी के दायरे में नहीं आता है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और मूल्य आयोग के अनुसार, 23 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका एमएसपी है। इनमें सात अनाज धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, पांच दालें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सात तिलहन मूंगफली, रापसीड-सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी शामिल हैं। कुसुम, नाइजर बीज, और चार व्यावसायिक फसलें खापरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। लेकिन सूची में लहसुन नहीं है।

गुणवत्ता से व्यापारी परेशान

लहसुन व्यापारी प्रदीप राठी ने कहा कि पहले मंडी कर बिक्री पर 0.5 प्रतिशत था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी एक कारण है कि हम बड़ी मात्रा में लहसुन खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर ऐसे समय में जब उत्पादन इतना अधिक है। अधिक उत्पादन किसानों के लिए भी परेशान कर रहा है। किसानों को लगातार तीन साल से अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन इस साल अधिक उत्पादन हुआ है। बारिश ने लहसुन को नुकसान पहुंचाया है।

किसानों ने सजाई लहसुन-प्याज की अर्थी

मग के किसान अपनी बढहाली के आंसू रो रहे हैं। जहां उन्हें अपनी फसल की लागत तक के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। लहसुन-प्याज के दामों ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। कृषि उपज मंडी में लहसुन 40 से 50 पैसे प्रति किलो बिक रही है। इससे आहत किसानों को अपना दर्द बयां करने के लिए अनेक प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। रतलाम जिले के सैलाना में किसानों ने लहसुन-प्याज की अर्थी सजा कर ढोल धमाके के साथ जुलूस निकाला और एसडीएम कार्यालय पहुंचे जहां किसानों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम एसडीएम मनीष कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा। अपनी उपज के उचित दाम दिलाने जाने की मांग की। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन हमें यहां आय तो दूर लागत तक का पैसा नहीं मिल पा रहा है।

घातक है थनैला रोग, उचित प्रबंधन से लगेगी रोक



डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी (म.प्र.)

थनैला रोग दुधारु पशुओं खासकर गाय तथा भैंस में बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह दुधारु पशुओं के अयन का एक बहुत ही घातक छूतदार रोग है, जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। यदि रोग के शुरूआती लक्षणों को देखकर इसका निदान नहीं किया जाता है तो यह पशु के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। यह रोग अयन से संबंधित है, अतः केवल मादा दुधारु पशुओं को ही होता है। इस रोग में पशु मरते कम हैं, परंतु अयन सूखकर थन सदैव के लिए बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से यह रोग बहुत क्षति पहुंचाता है।

थनैला रोग से लाखों पशु प्रतिवर्ष देश में बेकार होकर पशुपालक तथा राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आंकड़ों के अनुसार वलज्मान में थनैला रोग डेयरी पशुओं की मुख्य बीमारी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक थनैला रोग के शुरूआती लक्षणों को देखकर इस रोग की भयानकता का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और वह इलाज के लिए टोने-टोटकों में समय जाया करते रहते हैं। जिसके चलते यह रोग काबू से बाहर हो जाता है।

रोग की प्रारंभिक अवस्था में पशु के थनों पर सूजन की शुरूआती होती है, जिसे पशुपालक छूट्टर आदि के सूंघने के कारण होना समझकर थनों की गर्म पानी से सिकाई करते रहते हैं। इसके चलते रोग की तीव्रता और बढ़ जाती है। थनैला रोग पशु के अयन की संरचना एवं संक्रमण को दर्शाता है। इस रोग से दूध बनाने वाली एपीथिलियल कोशिकाएँ प्रभावित होकर या तो मर जाती हैं या दूध में विसर्जित हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप पशु कम दूध देना शुरू कर देता है। गाय-भैंसों में अधिकतर यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं द्वारा होता है, परंतु भारत में मुख्य रूप से इस रोग को फैलाने में स्टैफिलोकोकाई जीवाणु प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। थनैला रोग मुख्यतः पशु के खराब, गंदी, नमीयुक्त स्थान पर रखने अथवा बैठने से जीवाणु संक्रमण द्वारा पैदा होता है। इसके अलावा दुग्ध दोहन का गलत तरीका प्रयोग में लाने, पशु के थनों पर चोट अथवा रगड़ लग जाने, खराब सड़ा-गला चारा खिलाने और पशु के आवास में उचित सफाई व्यवस्था नहीं रखने से यह रोग हो जाता है। कई बार ग्वाले के गंदे हाथ, कपड़े, पशुओं के शरीर और पशुशाला की दीवारों भी इस रोग के फैलाने में सहायक होती हैं।

अधिक दूध देने वाले पशु इस रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वातावरण भी थनैला रोग को काफी हद तक प्रभावित करता है। बरसात के मौसम में अधिक तापमान एवं नमी तथा सर्दियों में कम तापमान एवं नमी के कारण पशु की अवरोधक क्षमता घट जाती है और पशु आवास में सफाई नहीं रहने की दशा में, गीलापन एवं गोबर होने की वजह से जीवाणु अधिक पनपते हैं। इस प्रकार के फर्श

पर लगातार बैठने से ये थनैला रोग का जीवाणु पशु के अयन में थनों की दुग्ध नलिका के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। अयन में प्रवेश करने के पश्चात् ये जीवाणु दूध के संपर्क में आकर और अधिक वृद्धि करते हुए कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप पशु थनैला रोग के विभिन्न लक्षणों को दर्शाता है। यह रोग गायों की अपेक्षा भैंसों में कम होता है। इसका



मुख्य कारण भैंसों की थनों की मजबूत मांसपेशी है जो जीवाणु को थन के सुराख में प्रवेश नहीं करने देती है। परंतु देखा जा रहा है कि दुधारु भैंसों में भी यह रोग बहुत तेजी से पनपने लगा है।

साधारणतया थनैला रोग अयन तक ही सीमित रहता है और तीव्र, कुछ तीव्र तथा दीर्घकालिक अवस्थाओं में पशु को होता है। तीव्र थनैली में तापक्रम का बढ़ना, बैचैनी, भूख में कमी, गर्म लाल तथा दर्द युक्त अयन, बाद में बढ़ती हुई सुस्ती, तापक्रम का गिरना, अयन ठण्डा तथा कड़ा होकर थनों से अचानक दूध का बहाव बंद हो जाना आदि इस अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। थनों से निकला दूध पहले पीलापन लेकर बाद में गहरे लाल रंग का हो जाता है। अयन ठण्डा, कड़ा तथा नीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। कुछ तीव्र थनैली के लक्षण तीव्र थनैली जैसे ही हैं। अंतर केवल इतना है कि वे धीरे-धीरे प्रकट होकर पशु को कुछ कम हानि पहुंचाते हैं। अयन से निकले दूध में

छीछड़े एवं पीलापन होता है। दीर्घकालिक अवस्था में इसके लक्षण बहुत ही धीरे-धीरे प्रकट होने के कारण रोग का आक्रमण होने के काफी दिनों बाद उसकी पहचान हो पाती है। इस अवस्था में अयन बड़ा होकर सख्त हो जाता है, दबाने पर दर्द नहीं होता है। थनों से निकला दूध पतला एवं छीछड़े युक्त होता है। धीरे-धीरे अयन क्षीण होकर, पशु का दूध कम होता चला जाता है। जो कि बाद में पूरी तरह आना बंद हो जाता है। थनैला रोग से प्रभावित पशु का इलाज तुरंत कराना चाहिए जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी न आये और रोग पर समय रहते रहते काबू पाया जा सके। थनैला रोग प्रमुख रूप से कुप्रबंधन से पैदा होता है।

रोग के बचाव एवं रोग होने की दशा में निम्न बातों पर अमल करना चाहिये: पशु आवास एवं दूध निकालने के स्थान को हमेशा साफ, स्वच्छ और सुखा रखें। पशु आवास में समुचित मात्रा में हवा, सूरज का प्रकाश एवं रोशनी आनी चाहिए। पशुशाला में हर सप्ताह क्रमशः चूने एवं पिनाइल के घोल का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे नुकसानदायक कीटाणु नष्ट होते रहें। पशुओं की देखभाल में लगे ग्वाले के हाथों, कपड़ों, दूध दुहने वाले बर्तनों, पशुओं के अयन आदि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। थनों एवं अयन पर सूजन की दशा में गर्म पानी अथवा गर्म सिकाई कदापि नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर बर्फ से ठण्डा सिकाई करनी चाहिए। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोयें। दूध की पहली धार को जांच करें, सामान्य होने पर ही बाट्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमेगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को एक-एक मिनट के लिए बारी-बारी से डुबायें। थनों पर झाग लगाकर दूध न निकालें, यदि ऐसा कर रहे हैं तो दुग्ध दोहन उपरंत लाल दवा से थनों को धोने के बाद चारों थनों पर एक भाग प्लिसरीन तथा एक भाग पोटेशियम परमेगनेट मिलाकर बनाई गई दवा लगाते रहना चाहिए। इससे थन नहीं चटकेंगे तथा चटके थन बहुत जल्दी ठीक हो जायेंगे।

बकरियों में स्वास्थ्य प्रबंधन

डॉ. ब्रजमोहन सिंह थाकड़ डॉ. सत्येन्द्र सिंह तोमर, डॉ. अजय राय, डॉ. रश्मि चौधरी

अन्य पशुधन के सामान बकरी पालन में पशु स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक क्षति झुण्ड के 50 प्रतिशत मृत्यु तथा निरोगी रहें। यदि वे अस्वस्थ या बीमार हो जाए, तो उनके रोग को पहचान कर तत्काल उपचार करें। इससे बकरियों को मृत्यु से बचाकर आर्थिक हानि से बचा जा सकता है। बकरियों में पी.पी.आर., ई.टी., खुरपका मुहँफका, गलघोट्ट तथा बकरी चेचक रोगों के टीके अवश्य लगवाने चाहिए। कोई भी टीका 3-4 माह की आयु के उपरंत ही लगाया जाता है। इसलिए बरसात आते ही इन्हें रोगों से बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ये सभी रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। इन रोगों के लक्षण देखते ही यथा शीघ्र उपचार के उपाय करने चाहिए। इन रोगों का देसी इलाज भी प्रभावी होता है। पशु चिकित्सक को दिखाकर उपचार कराया जा सकता है। अंतः परजीवीनाशक दवा वर्ष में दो बार पिलानी चाहिए (एक वर्षा से पूर्व दोबारा वर्षा के उपरंत)। बाह्य परजीवीनाशक दवा से सावधानीपूर्वक बकरियों को छान कराने से परजीवी मर जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं रोग का मूल्यांकन: किसी भी बीमारी, समस्या या संक्रमण को सही ढंग से पहचानने के लिये प्रत्येक झुण्ड के पशुपालक को प्रतिदिन पूरे झुण्ड का मुआयना करना चाहिए। नीचे दिए गए सार्वजनिक नियम अच्छे तरीके से प्रति दिन करना चाहिए जिससे स्वस्थ एवं अस्वस्थ पशु को पहचान कर उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए

तापमान - 101.5-103° सेंटी

दिल की धड़कन- 70-80 प्रति मिनट

सांस लेने की गति- 12-15 प्रति मिनट

बकरी की जवान होने की आयु- 8-12 महीने

कामोत्तेजना में बकरी की गर्म रहने की अवधि-12-72 घण्टे

कामोत्तेजना चक्र अवधि- 18-22 दिन

ग्याबन कल की अवधि- 5 महीने या 150 दिन

अस्वस्थता के संकेतक:अस्वस्थ बकरी अपने आपको झुण्ड से अलग कर लेती है। बकरी का आवरण घटिया या खराब हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही खांस और कंपकंपी दिखाई देती है। पशु को भूख नहीं लगती, जुगाली नहीं करता, पेट पूंज जाता है कुछ भी चबा पाने में असमर्थ हो जाता है। मुँह से लगातार लार बहती रहती है और झाग निकलता है। आँवों की श्लेष्मा का लाल हो जाती है।



अस्वस्थता के परिणाम: लंबे समय तक बीमारी से ग्रस्त रहने पर बकरियों के उत्पादन और शारीरिक भार में कमी आती है जिसके साथ दुर्बलता आती जाती है। पशु की प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। बाड़े में मृत्यु दर अधिक होने पर आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो जाता है।

बकरी में होने वाली बीमारियों के कारक: बकरी में बीमारियाँ विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, कृमि, बाह्य परजीवी, शारीरिक चोट, असंतुलित पोषण, पोषक तत्वों की कमी आदि से होती है।

बीमारियों से बचाव: प्रतिदिन सुबह बकरियों की जांच करें जो बकरी बीमार हो उसे बाकी बकरियों से अलग करें। अन्यथा दूसरी बकरियों में रोग फैलने की संभावना रहती है।

- » बीमारी बकरियों को चरने के लिये ना छोड़े।
- » हर तीन महीने में बकरियों को कृमिनाशक दवाई पिलायें।
- » हर चार महीने में बकरियों को खुजली से बचाने के लिए कृमिनाशक दवाई से नहलायें।
- » बरसात के दिनों में बकरियों के कोठे की जमीन पर चूने का छिड़काव करें।
- » हर तीन महीने में कोठे की दीवार पर चूने से पुताई करें।
- » बकरियों का नियमित रूप से टीकाकरण करवायें और कृमिनाशक दवाई पिलायें।

बकरी स्वास्थ्य के संबंध में याद रखने योग्य सुझाव: सामान्य पशुओं की देखभाल में निहित है-अच्छा पोषण, शेल्टर, प्रजनन, खुर्शों की देखभाल, समय . समय पर करनी चाहिए ।

कृमिनाशक दवापान अदि समय-समय पर करनी चाहिए । अस्वस्थता से कम उम्र की बकरियों की वृद्धि घट जाती है और वयस्को का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे की उत्पादन दर एवं चिकित्सा दर बढ़ जाती है। नवजात बच्चे दूध से वंचित होने, खराब सफाई व्यवस्था और पोषण के कारण बीमारियों और संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। बीमार पशुओं को पहचानकर अलग रखने के साथ ही उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बीमारी या रोग ग्रस्त पशु को स्वस्थ पशु के साथ तभी सम्मिलित करना चाहिये, जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाये व सामान्य खान- पान करने लगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिये नित्य देखभाल के साथ ही अच्छा प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिसके तहत बीमारियों का उचित उपचार, डिवर्मिंग और टीकाकरण आते हैं।

अरहर की भूसी में होता है दूध छह गुना ज्यादा कैल्शियम

अरहर/तुअर के बीजावरण यानी उसकी भूसी में दूध की तुलना में छह गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन उसके बावजूद या तो उसे फेंक दिया जाता है या फिर उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ऐसे में इसके गुणों को देखते हुए माना जा रहा है कि इसका उपयोग खाद्य और दवा उद्योगों में किया जाता है जो एंस्टियोपोरोसिस और रिक्तदस जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह जानकारी इंटरनेशनल क्राफ्ट रिचर्स इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रांजिक्स (इक्रोसेट) द्वारा की गई रिचर्स में सामने आई है जिसके निष्कर्ष पीयर-रिव्यू जर्नल सरटेनेबिलिटी में प्रकाशित हुए हैं। इक्रोसेट के मुताबिक अरहर के दानों में बीजावरण की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी होती है जोकि दाल उद्योग से प्राप्त होने वाला एक उप-उत्पाद होता है। देश में इसके ज्यादातर हिस्से को या तो वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है या फिर उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। शोध से पता चला है कि अरहर के केवल 100 ग्राम बीजावरण में करीब 652 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि दूसरी तरफ 100 मिलीलीटर दूध में कैल्शियम की मात्रा 120 मिलीग्राम ही होती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इंसान को हर दिन औसतन 800 से 1,000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जबकि शोध से पता चला है कि भारतीयों को उनके आहार से औसतन उतनी मात्रा नहीं मिल पा रही है। रिचर्स के मुताबिक अरहर को आमतौर पर दक्षिण एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है जोकि एक प्रमुख दलहन फसल भी है। भारत की बात करें तो वो दुनिया भर में अरहर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2020 में दुनिया की 82 फीसदी अरहर भारत में पैदा की गई थी।

देश में 69 लाख लोगों की कैल्शियम सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर सकता है यह कच्चा: शोध के मुताबिक 2020 में कुल 38.9 लाख टन अरहर का उत्पादन हुआ था, जिसकी मिलिंग के बाद करीब 3.9 लाख टन बीजों की भूसी प्राप्त हुई थी। देखा जाए तो इस 3.9 लाख टन भूसी में 2,543 टन कैल्शियम प्राप्त हो सकता है, जोकि प्रति व्यक्ति 1,000 मिलीग्राम की दर से 69 लाख लोगों की एक साल की कैल्शियम सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

-एक जिला-एक उत्पाद में फसल आधारित 363 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयां स्थापित

सीएम बोले-पान की खेती के लिए किसानों को कर रहे प्रोत्साहित

उद्यानिकी फसलों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग मिशन मोड पर करो

भोपाल। जगत गांव समार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक जिला-एक उत्पाद योजना में जिलों में उद्यानिकी फसलों और उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की गतिविधियां मिशन मोड पर की जाए। प्रदेश में 363 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रधानमंत्री खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में 212 और राज्य योजना में 151 इकाइयां स्थापित जा चुकी हैं, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यानिकी विभाग दीर्घकालीन लक्ष्य में पोटेटो टिशू कल्चर एवं एरोपोनिक लेब, हाईटेक फ्लोरोकल्चर नर्सरी स्थापित करने और 1500 सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण इकाइयां लगाने के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयास बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने निवास पर उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जेएन कंसोर्टिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती क्षमता- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकसित 14 लाख 28 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विकास का कार्य हो चुका है। इस वर्ष 25 हजार मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य पूरा करने पर फोकस किया जाए। उद्यानिकी विभाग के अल्पकालीन लक्ष्यों में माइक्रो इरीगेशन बढ़ाने, किसानों के खेतों पर चैनलिक फेसिंग, नर्सरी गौ-शालाओं के कन्वर्जेंस से जैविक बागवानी, कृषक प्रशिक्षण, माली प्रशिक्षण और उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार के कार्यों को समय-समय में पूर्ण किया जाए। वित्त वर्ष के अंत तक संभाग और विकासखंड स्तर पर कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और मुर्ना में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस प्रारंभ करने का कार्य भी पूर्ण किया जाए।



दस जिलों में बनेंगे ग्रीन हाउस वलस्टर

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और विविधीकरण, कृषि अधो-संरचना के प्रयास, प्रमाणित जैविक उत्पादन में वृद्धि, कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों का मूल्य संवर्धन और अतिरिक्त रोजगार के लिए मत्स्यपालन, रेशम पालन विकास और मधुमक्खी पालन के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इस वर्ष सीहोर, ग्वालियर और मुर्ना में इनक्यूबेशन सेंटर्स का भूमि-पूजन किया गया है। बैतुल जिले में शेडनेट निर्माण का क्लस्टर विकसित किया गया। प्रदेश के दस जिलों भोपाल सहित सीहोर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, खरगोन जबलपुर और छिंदवाड़ा में ग्रीन हाउस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

पान की खेती को प्रोत्साहन

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में किसानों को पान की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष रूप से बुंदेलखंड अंचल में सागर और छतरपुर जिले में किसान इसके लिए आगे आए हैं। वर्ष 2021-22 में 520 हितग्राहियों को प्रतिइकाई 29 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्तमान वित्त वर्ष में भी हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

सब्जी, पुष्प और मसाला का विस्तार

प्रदेश में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 13 हजार 328 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार का कार्य हो रहा है। फल, पौध-रोपण में आम, अमरूद, नींबू, काजू, अनार, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, केला, आंवला और संतरा का उत्पादन 2 हजार से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। सब्जी विस्तार क्षेत्र में फसल विविधीकरण का कार्य हो रहा है। इनमें टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गिलकी, लोकी, भिंडी आदि का उत्पादन लिया गया है। गतवर्ष की तुलना में सब्जी के साथ ही पुष्प क्षेत्र और मसाला क्षेत्र का विस्तार गतवर्ष की तुलना में 6.45 प्रतिशत अधिक हुआ है। प्रदेश में 137 उद्यानिकी नर्सरियों को स्व-सहायता समूहों से पीपीपी मोड पर सुदृढीकरण के लिए चयनित किया गया। इससे 93 लाख 75 हजार पौधे तैयार किए गए।

-आयुष राज्य मंत्री कावरे ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

किसानों को औषधीय खेती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

-अधिकारी-कर्मचारी घर पर लगाए 15 किस्म के औषधीय पौधे

भोपाल। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर कावरे ने कहा है कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिये औषधीय खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये देवारण्य योजना शुरू की गई है। योजना में किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है। राज्य मंत्री भोपाल के प्रशासन अकादमी में औषधीय पौधों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद का महत्व हम सभी को कोरोना महामारी के दौरान पता चला, जब एलोपैथी भी काम नहीं आई और आयुर्वेद से लोग स्वस्थ हुए। कोरोना महामारी में आयुर्वेदिक क्रिकेट चूर्ण एवं आरोप्य कसायाम का उपयोग करते हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें स्वस्थ किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिये औषधीय पौधों की पहचान

और उसके उपयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। कावरे ने कहा कि आयुर्वेद औषधियों की पैकेजिंग में और सुधार की आवश्यकता है। नई टेक्नालॉजी से पैकेजिंग में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निवास के परिसर में कम से कम 15 किस्म के औषधीय पौधे लगाएं। संगोष्ठी के संयोजक दिलीप कुमार ने विभिन्न सत्रों की जानकारी दी। प्रबंध संचालक लघु कुमार गुप्ता मौजूद थे। संरक्षक रमेश कुमार गुप्ता मौजूद थे। तकनीकी-सत्र में आरजीपीव्ही विश्वविद्यालय की डॉ. दीप्ति जैन, केन्द्रीय आयुर्वेद संस्थान मुम्बई के डॉ. आर. गोविंद रेड्डी ने हर्बल औषधियों की गुणवत्ता और उसके पैरामीटर मापने की जानकारी दी। पुणे के डॉ. रविन्द्र धनेश्वर ने हर्बल औषधियों के प्रमाणीकरण, दस्तावेजीकरण और मानकीकरण के बारे में बताया।

मप्र में उन्नत कृषि के संबंध में कृषि मंत्री ने इजराइली राजदूत से की चर्चा

» शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा सेंटर फॉर एक्सिलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि इजराइल हमारा दीर्घकालीन सहयोगी रहा है। मंत्री श्री पटेल ने नई दिल्ली के इजराइल दूतावास में इजराइली राजदूत नाओर गिलोन और प्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश में उन्नत कृषि के संबंध में वार्ता की। इजराइली प्रतिनिधियों ने आश्चर्य किया कि हर्दा में सेंटर फॉर एक्सिलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने इजराइल की उन्नत कृषि और जल प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ नॉलेज शेयरिंग से प्रदेश को लाभ मिलेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश का हर्दा जिला उपयुक्त और महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। हर्दा में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। इजराइली तकनीक का सहयोग मिलने से निश्चित की हर्दा के साथ प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा।

दो दिवसीय दौरे पर मप्र आए कृषि सचिव मनोज आहूजा

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में एसीएस कृषि मध्यप्रदेश शासन श्री अजीत केसरी, कृषि संचालक श्रीमती प्रीति मैथिल ने भारत सरकार की और से जो भी नयक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एमडी जी वी रश्मि, बीज निगम के प्रबंध संचालक तरुण राठी के साथ-साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में माननीय सचिव महोदय के समक्ष मध्यप्रदेश में कृषि से संबंधित नवाचारों की प्रस्तुति की गई। जिसमें मुख्य रूप से ई-अनुज्ञा प्रणाली, एमपी फार्म गेट एप, एआईएफ योजना अंतर्गत कार्यों की प्रस्तुति के साथ-साथ मध्य प्रदेश से हुए कृषि निर्यात के बारे में विस्तार से जानकारी कृषि सचिव को दी गई प्रस्तुति के अवलोकन उपरत कृषि सचिव द्वारा मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग तथा

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा उक्त कार्य के लिए मध्यप्रदेश शासन तथा बोर्ड को शुभकामनाएं दी। कृषि तथा कृषकों के विकास के लिए किए जा रहे उक्त कार्यों में भारत सरकार की और से जो भी नयक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एमडी जी वी रश्मि द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।



मध्यप्रदेश में कृषि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ किसानों को मिले

» मुख्यमंत्री शिवराज ने की कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा, बोले

» कृषि विविधीकरण की परियोजनाएं अमल में लाने की उपलब्धि अहम

भोपाल। जगत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि के इच्छुक किसानों के साथ शीघ्र ही संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 59 हजार किसानों के पंजीयन और 28 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के कार्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया, फार्म गेट एक्ट की पहल और कृषि क्षेत्र में उन्नति एप के प्रयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए मध्यप्रदेश में दो परियोजनाओं की स्वीकृति एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। वर्तमान में आईटीसी द्वारा औषधीय अश्वगंधा और तुलसी के 4500 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन के साथ ही ग्रीन एंड ग्रेंस का जैविक सब्जियों और अनाज का 1235 एकड़ में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है। चार अन्य परियोजनाओं पर परीक्षण की कार्यवाही चल रही है। इनमें विदिशा जिले में हरी मटर और धनिया, रीवा, सतना, ग्वालियर, देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में आलू उत्पादन, देवास में बांस उत्पादन और नर्मदापुरम, सीहोर एवं छिंदवाड़ा में संतरा और अमरूद का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास है। कृषि विविधीकरण में मध्यप्रदेश में किए गए ठोस प्रयास जारी रखे जाएं। प्रदेश में 3 साल में सरसों का उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्तमान में 12 लाख 33 हजार हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन हो रहा है।

28 हजार किसानों को सरकार ने पढ़ाया जैविक खेती का पाठ



बैठक में बताया गया कि प्रदेश में तरल अर्थात नैनो यूरिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इफको के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन से करीब एक हजार एकड़ कृषि क्षेत्र में नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का अभिनव प्रयोग किया गया। करीब 400 किसानों द्वारा इसे अपनाया गया। खरीफ 2022 में अब तक 6 लाख 7 हजार बोतल से अधिक नैनो तरल यूरिया का विक्रय किसानों

को किया गया है। रबी 2021-22 में 16 लाख 11 हजार लाख बोतल नैनो तरल यूरिया का विक्रय किसानों को किया गया। इसका प्रचार निरंतर बढ़ रहा है। विक्रेता, समितियों के सदस्य और कृषि विभाग के माध्यम से यह प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में संपन्न कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानते हुए इन कार्यों को देश में स्थापित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा।

यूरिया, डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि साह्य में एक दिन आगनेवाड़ी केंद्रों में बच्चों को और मध्याह्न भोजन में विद्यार्थियों को मोटे अनाज जैसे कोले-कुटकी के वितरण से आमजन भी मोटे अनाज के महत्व से परिचित होगा। मोटे अनाज का पोषण की दृष्टि से अधिक महत्व है। गेहूँ के निर्यात के साथ अन्य उत्पादों के निर्यात के प्रयास भी बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 116 एफपीओ कार्यरत है। कृषि अवसरचना निधि के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। बैंकों ने अब तक 3422 आवेदन सत्यापित कर 1878 करोड़ रूपए की राशि वितरित की है। प्रदेश में यूरिया, डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

वास्तविक मछुआरों को आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास करें

राज्य की लोकप्रिय मछली की किरमों को बाजार तक पहुंचाएं

भोपाल। जगत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मछुआरों के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए प्रयास थमना नहीं चाहिए। प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य-संपदा उपलब्ध है। मत्स्यखेट से जुड़े पारंपरिक मछुआरों को आर्थिक लाभ के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्हें उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग का कार्य भी किया जाए।

प्रदेश में झींगा उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में हो रहा है। इसके विक्रय के लिए बाजार में बेहतर व्यवस्थाएं और झींगा पालकों को उसका फायदा दिलाने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठकों के क्रम में मछुआ-कल्याण तथा मत्स्य-विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। जल संसाधन और मछुआ-कल्याण एवं मत्स्य मंत्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल में होगी मछुआ पंचायत

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 29 मई को उनके मछुआरों से संवाद कार्यक्रम में मछुआरों को मत्स्य-पालन और मत्स्यखेट के लिए आवश्यक उपकरण, नवीन तकनीक से निर्मित जाल, आइस बॉक्स सहित मोटर साइकिल प्रदान की गई थी। इससे मछुआरों को अपने कार्य में आसानी के साथ आर्थिक लाभ मिल रहा है। शीघ्र ही भोपाल में राज्य-स्तरीय मछुआ पंचायत होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य मछली महाशीर के अलावा रोहू एवं अन्य लोकप्रिय मछली प्रजातियों को अन्य राज्यों के बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए।



अपात्र सदस्यों को हटाया

जानकारी दी गई कि प्रदेश में मछुआरों के स्थान पर बाहरी लोगों द्वारा जलाशयों में प्रबंधन और मत्स्य-पालन पर रोक की कार्यवाही की गई है। कुल 1745 मत्स्य सहकारी समितियों की जांच कर अपात्र लोगों को समितियों से बाहर किया गया है। प्रदेश में 14 हजार से अधिक अपात्र सदस्य निष्कासित किए गए हैं।

मत्स्य-बीज और मत्स्य-उत्पादन दोनों बढ़े

बताया गया कि प्रदेश में वार्षिक मत्स्य-बीज उत्पादन 145 करोड़ मानक फाई से बढ़ा कर 200 करोड़ मानक फाई किए जाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास किए गए। वर्ष 2020-21 में मत्स्य-बीज उत्पादन में 148 करोड़ मानक फाई की उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2021-22 में 171 करोड़ मानक फाई की उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में जुलाई माह तक 103 करोड़ मानक फाई की उपलब्धि अर्जित कर ली गई है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 200 करोड़ मानक फाई से अधिक उपलब्धि अर्जित करने का प्रयास है। प्रदेश का मत्स्य-उत्पादन जुलाई माह तक 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन हो चुका है। गत दो वर्षों में यह क्रमशः 2.48 लाख टन और 2.93 लाख टन था। वर्तमान वित्त वर्ष में यह उत्पादन लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन रहेगा।

प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में योजना क्रियान्वयन का लक्ष्य

मप्र के 5,200 गांवों में होगी प्राकृतिक खेती मप्र प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू

भोपाल। जगत गांव हमार

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि पेस्टीसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मुदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण-संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना निहायत ही जरूरी है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी जिलों में 100-100 ग्रामों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक चयनित कर उन्हें गौ-पालन के लिये अनुदान भी दिया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक कृषि प्रारंभ होगी। प्रत्येक ग्राम से 5 प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का चयन करेंगे। चयनित कुल 26 हजार किसानों को गौ-पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। ग्रामों में वे ही किसान सम्मिलित होंगे, जिनके पास देशी गाय होंगी। सभी वर्गों के कृषकों को न्यूनतम एक एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि करने की अनिवार्य शर्त पर मात्र एक गाय के लिए 900 रूपए प्रतिमाह की अनुदान राशि दी जाएगी। मंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि से लोगों को रसायन मुक्त शुद्ध और पोषिक खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे।



किसानों का पंजीयन किया जाएगा

अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास अर्जीत केसरी ने बताया है कि योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए आत्मा योजना के शत-प्रतिशत क्षेत्रीय मैदानी अमले को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि के लिए पोर्टल/मोबाइल एप भी तैयार कर विभागीय अमले के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि करने के इच्छुक किसानों को पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों में से प्रत्येक विकासखंड में 5 प्रगतिशील अग्रणी कृषकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित कर प्रशिक्षित किया जाएगा।

कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

प्रशिक्षण के बाद मास्टर ट्रेनर प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे। इन्हीं प्राकृतिक प्रेरक द्वारा पोर्टल/मोबाइल एप पर पंजीकृत प्राकृतिक कृषि करने के इच्छुक सभी कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एपीएस केसरी ने बताया कि जिला स्तर पर आत्मा के परियोजना संचालक द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। विकासखंडवार चयनित हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन आत्मा की गर्बिनग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। योजना की मॉनिटरिंग का कार्य मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में गठित राज्य एवं जिला स्तर की समितियां करेंगी।

गेहूं व जौ की नई किस्मों को मप्र के लिए किया जा रहा जारी

प्रदेश में कठिया गेहूं की नई किस्मों से दूर होगा कुपोषण

-38 डि.सें. तापमान पर भी गेहूं व जौ का उत्पादन होगा अच्छा

इंदौर | जागत गांव हमार

मध्य प्रदेशवासियों को जल्द ही कठिया गेहूं की उन्नत किस्म मिलने वाली है। इसके आटे, रवे, दलिया, पास्ता, मैकरोनी के सेवन से शरीर में प्रोटीन, जिंक व आयरन की कमी पूरी होगी। इस किस्म से उत्पादन अधिक होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इंदौर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. जेपी सिंह बताते हैं कि हाल ही में कठिया गेहूं की दो उन्नत किस्में तैयार की गई हैं। यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देंगी और रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व दिन का तापमान 38 डिग्री होने पर भी पैदावार में कोई फर्क नहीं आएगा। करनाल में भी इसी तरह की वैरायटी तैयार की गई है। यह दोनों ही किस्में किसानों के लिए जारी की जा रही हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत को कुपोषण मुक्त बनाएगा। खास बात यह है कि यह नई किस्म रोग मुक्त है और मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से इनकी यहां पर पैदावार अधिक होगी।



पूसा वकुला 1663

यह वैरायटी एचआइ 1663 पूसा वकुला हाल ही में इंदौर के आईएआरआई रीजन स्टेशन में तैयार की गई है। इस वैरायटी से तैयार गेहूं की चपाती अच्छी बनती है। इसका उपयोग ब्रेड व बिस्कुट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसकी पैदावार 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह सिंचित क्षेत्र में ही अच्छी पैदावार देती है, इसके लिए कम से कम पांच से छह पानी देने की आवश्यकता है।

इन किस्मों का बीज जल्द मिलेगा

इस साल करनाल की डीबीडब्ल्यू 296, 327, पवारखड़ा की मपी/जेडब्ल्यू/1358, बीएचयू वाराणसी एचयूडब्ल्यू 838, रांची का बीआईआरएसए जीईएचयूएन-4 और गुजरात की जीडब्ल्यू 513 जारी की गई है, जो जल्द ही किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

कठिया गेहूं की वैरायटी

» एचआई 8823: पूसा प्रभात इंदौर के आइएआरआई रीजन स्टेशन में तैयार की गई है।
» डीडीडब्ल्यू 47, 48: करनाल में तैयार की गई है।

कठिया गेहूं की खासियत

» कम सिंचित क्षेत्र में पैदावार भरपूर
» दो पानी देने पर अच्छी पैदावार
» आठ क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन
» 115 से 125 दिन में फसल पककर तैयार
» नवंबर में बुवाई शुरू कर सकते हैं

यह बायोफोर्टी फाइड किस्में हैं

» प्रोटीन-12 पीपीएम/पाट पर मिलियन
» जिंक-38 पीपीएम तक
» आयरन-43 पीपीएम से अधिक
» पीला तत्व-7 पीपीएम

तुर्की के बाजरा की मुरैना में खेती

पैदावार को लेकर किसानों में उत्सुकता, 11 फीट लंबा तना और तीन फीट बाली

मुरैना। मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के सिमरौदा अहौर गांव के एक किसान ने तुर्की से मंगवाए बाजरा के बीज की खेती की है, जो किसान ही नहीं कृषि वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। इस बाजरा के पौधे का तना आम बाजरा से डेढ़ गुना तो बाली दो से छह गुना लंबी है। जिला मुख्यालय से 70 किमी दूर सबलगढ़ तहसील के रामपुरकलां क्षेत्र के सिमरौदा अहौर गांव में रहने वाले युवा किसान विश्वंभर यादव ने बताया कि डेढ़ बीघा खेत में तुर्की के बाजरा की खेती की है। राजस्थान में रहने वाले दोस्त के जरिए तुर्की बाजरा का एक किलो बीज मंगवाया। बोवनी जून के दूसरे पखवाड़े में की थी। अब पौधे 14 फीट तक लंबे हो गए हैं। 11 फीट का तना और तीन फीट तक लंबी बालियां हैं, जबकि स्थानीय बाजरा के पौधे का तना 6 से 7 फीट तक और बाली एक से डेढ़ फीट तक होती है। मुरैना से लेकर रघोपुर तक के किसान इस बाजरे को देखने आ रहे हैं।

पैदावार ज्यादा होने की उम्मीद

देशी बाजरा की फसल तीन माह में पककर तैयार हो जाती है, पर तुर्की के बीज से तैयार हुई बाजरा की फसल इससे पहले ही पककर तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके पौधे में तीन-तीन फीट तक की बालियां आ गई हैं। अभी बालियों में फूल व दाना बिखरा-बिखरा है, फसल पकने के साथ बालियों में दाना घना व बड़ा होने का दावा किया जा रहा है। तुर्की के बाजरे का पौधा भी इतना मजबूत है कि उसके तने की मोटाई एक इंच की है, इसलिए मवेशियों को निकलने वाले चारे (कब) की पैदावार भी बढ़ना तय है पर अनाज का उत्पादन व गुणवत्ता कैसी होगी। यह बाजरा की फसल पकने बाद ही पता लगेगा।

11 फीट का तना है तो मवेशियों को चारे की पैदावार तो इस बाजरे से खूब होगी, लेकिन तीन फीट लंबी बाली से अनाज की पैदावार तो फसल का उत्पादन होने पर ही पता लगेगी। इस फसल पर हमल जकरी शोध करेंगे। अगर पोषण तत्व और अच्छी उपज रहती है तो क्षेत्र के अन्य किसानों को भी सलाह देंगे कि अन्य किसान अपने खेतों में इस बाजरा की खेती करें। डॉ. एसएस तोमर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, मुरैना

नई किस्म से लाभ

गेहूं की पैदावार बढ़ाने व रोग मुक्त रखने के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग अधिक होता है, जो अब नहीं होगा या कम से कम करना होगा। प्रोटीन, आयरन व जिंक की उपलब्धता होने से कठिया गेहूं से तैयार होने वाला दलिया लोगों के लिए काफी लाभप्रद होगा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण होगा। क्योंकि कठिया गेहूं का दलिया, आटा, सूजी का आदि खून बढ़ाने का काम करेंगे। बच्चों के लिए मनपसंद खाना पास्ता, मैकरोनी आदि में भी प्रोटीन व आयरन जिंक भरपूर मिलने पर बच्चों में इनकी कमी को दूर करेगी।

कठिया गेहूं की जो किस्में तैयार की गई हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जारी किया जा रहा है। पैदावार के लिए जल्द ही बीज की उपलब्धता कराई जाएगी। कठिया गेहूं का सेवन लोगों स्वस्थ बनाएगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, करनाल

यूरिया की कमी, ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पैदा कर रहा समस्याएं

जबलपुर | जागत गांव हमार

जिले के विभिन्न विकासखंडों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन हर जगह से उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। कालाबाजारी किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो-नालत है। लेकिन ग्राउंड-जीरो पर उतर कर बात करने से हेरत में डालने वाली जानकारी सामने आई। वास्तव में उर्वरकों की कमी और फिर शुरू होने वाली कालाबाजारी के पीछे सबसे बड़ा कारक कोई और नहीं बल्कि किसान ही है। जरूरत से ज्यादा उर्वरकों के उपयोग ने इस समस्या को खड़ा किया है। इससे प्रत्यक्षतः तो किसानों का आर्थिक शोषण ही समझ में आता है, लेकिन इसके नई अन्य नुकसान भी हैं। इन दिनों जिले के 95 प्रतिशत से ज्यादा किसान धान की खेती कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत शेष हैं, उन्होंने मूंग-

उड़द या मक्का लगा रखा है। मूंग-उड़द के लिए तो फर्टिलाइजर की आवश्यकता है नहीं और मक्का भी समाप्त होने की स्थिति में है। ऐसे में केवल धान के लिए ही, वह भी मात्र यूरिया की आवश्यकता होगी। अधिकतर किसान पहले दौरे का छिड़काव कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। जिले के पांचों डबल-लाक केंद्रों पर यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहां से प्रत्येक किसान को एक बार में दो बोरी (एक क्विंटल) यूरिया ही दी जा रही है। इस तरह से कोई भी किसान एक महीने में अधिकतम 50 किलो तक यूरिया ले सकता है। डबल-लाक केंद्रों के अलावा जिले में कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से भी यूरिया और डीएपी का विक्रय किया जा रहा है। जिले में यूरिया और डीएपी की सप्लाई पिछले वर्ष से ध्यान की जा चुकी है।

भूमि को हो रहा नुकसान

किसानों द्वारा अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए जाने से भूमि की उर्वरता भी समाप्त होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह से किसानों द्वारा अधिक मात्रा में यूरिया डाले जाने से पौधा जल्दी हरा-भरा दिखने लगता है, जिसकी वजह से उस पर कीट-पतंगों का आटेक भी तेजी से होता है। इससे बचने के लिए किसान को पेस्टीसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने के बाद किसान को उपज उतनी ही मिल पाती है, जितनी प्रति एकड़ में 75 से 80 किलो यूरिया के इस्तेमाल से मिलती है।

डबल लाक सेंटरों की कमी

जिले में केवल पांच डबल लाक सेंटर ही प्रशासन की ओर से संचालित हैं। ये केंद्र जबलपुर, सिहोरा, मझौली, पाटन और शहदुरा में हैं। इस वजह से किसानों को लम्बी दूरी तय करके सेंटर तक पहुंचना पड़ता है। कई बार तो किसान को कालाबाजारी के बाद जितने में यूरिया उसके गांव के नजदीक मिल जाता है, उतने से ज्यादा भाड़ा सेंटर से दोहरा गांव तक लाने में लग जाता है। यह भी एक वजह है कि किसान समय और भाड़ा बचाने के चक्र में कालाबाजारी करने वालों के चंगुल में उलझा रहता है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नम्बर-9300034195
राहसेल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रवर्द्धक लाल-9925669304
विदिशा, अखेश दुबे-9425148554
सागर, अनिल त्रिवेदी-9266021098
राहलगाह, मन्वान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा-9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन-9895383522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा-9981462162
बेतूल, सतीश शर्मा-982777449
मुरैना, अखिल टण्डेडिया-9425128418
सिधपुरी, क्षेत्रराज मौर्य-9425622414
मिण्ड-नीरज शर्मा-9826266571
बलराम, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक जैन-9923800613
कैलाश, हरदत्त मिश्रा-9425000670
राहमन, अमित मिश्रा-7000714120
झुझम-नेमन धाम-8770736295



कार्यालय का पता- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसी बैंक के पास, एमपी नगर, जौन-1, भोपाल, मप्र, संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589